Mr. Speaker: In the statement of work for the next week they are not included. The hon. Member only wants to know when they are likely to be taken up.

Shri G. B. Pant: I think they can be taken up after the voting of Demands If they can be taken up earlier, we have no objection. Obviously., there is no time.

12.33 hrs.

DELHI LAND HOLDINGS (CEILING) BILL—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shrimati Violet Alva on the 24th February, 1960, namely:—

> "That the Bill to provide for the imposition of a ceiling on land holdings in the Union territory of Delhi and for matters connected therewith, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."

I think, Shri P. R. Patel was in possession of the House. Is he here?

An Hon. Member: He had finished, Sir.

Mr. Speaker: Shrimati Alva.

The Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri Datar): Shall I reply, Sir?

Mr. Speaker: Yes; only 14 minutes are left.

Shri Datar: Last time the Deputy-Speaker gave a ruling.......

Mr. Speaker: Let me hear him then.

Sardar Hukam Singh (Bhatinda): Last time there was a demand from many hon. Members who wanted to speak on this for an extension of time. I had announced that as all the three Bills had three hours each—there were nine hours in all—keeping that overall limit in view, we can discuss this Bill for some time more and then cut short the time in the other Bills. It was agreed, as there were some other hon. Members who wanted to speak on this and as less time will be taken on the other Bills, we may exceed the time-limit on this Bill.

Mr. Speaker: Nobody got up.

Several Hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: So, there are so many hon. Members who want to speak. Then, how much time has to be extended?

Shri Datar: I have to reply.

Mr. Speaker: There are hon. Members other than those from Delhi. How are they interested?

Some Hon. Members: It is the principle involved, Sir.

Shri Datar: The question of ceiling is common to all. That is the reason why more time is taken here.

Shri Naushir Bharucha (East Khandesh): We can carry on till 2.30 today, Sir.

Mr. Speaker: We shall carry on till Private Members' business is taken up. The Tripura and Manipur members may also speak on the question of ceiling. Whatever time is taken up here will be cut down in the others.

Shri Radha Raman.

श्री राधा रमण (चांदनी चौक): अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो प्रवर समिति से आया है उस में कई ऐसे सुधार हुए हैं कि जिन सुधारों को सामने रख कर सदन में जो पहले विचार रखे गये थे वह विचार अब कायम नहीं रहने चाहियें ऐसा मैं समझता हूं ।

[श्री राधा रमण]

13 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair].

वैसे इस विधेयक को विचार में लाते हुए बहुत से हमारे मित्रों ने कई बातों पर आपत्ति की है जिन पर पहले भी काफ़ी चर्चा हो चुकी है और मैं नहीं समझता कि इस की जरूरत थी कि उन्हें बार बार सामने लाया जाता। सीलिंग का क्वैश्चन सारे देश में बहुत महीनों से आ रहा है, और सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि इस कृषि प्रधान देश में सीलिंग का होना आवश्यक है। अन्य प्रान्तों में भी इस प्रकार के विधेयक पास हुए हैं जिनके द्वारा उन प्रान्तों में सीलिंग लगायी गयी है। हमारी दिल्ली टैरीटरी में भी, जब यहां पर लेजिस्लेचर था, तो एक लैंड रिफ़ार्म बिल लाया गया था और उसे पास किया गया था। उस वक्त भी इस सीलिंग की चर्चा थी और यह ख्याल जाहिर किया गया था कि लैंड पर सीलिंग लगाया जाए। परन्तु दुर्भाग्य से वह लेजिस्लेचर नहीं रहा और दिल्ली एक यूनियन टैरीटरी बन गयी।

जरूरत समझी गयी कि हमारे सदन में इस प्रकार का एक क़ानून लाया जाए और सीलिंग मुकर्रर की जाए। उसी के अनुसार यहां पर यह लैंड होल्डिंग सीलिंग बिल पेश किया गया था सन् १९५९ में और प्रवर समिति के सिपुर्द किया गया। जो विचार सदन के सभासदों ने सामने रखे थे उनको ध्यान में रख कर इसमें संशोधन हुआ है। मैं यह नहीं कहता कि यह बिल हर प्रकार से मुकम्मल है और जितनी भी आपत्तियां उस वक्त की गयीं थीं वे सारी की सारी इसके अन्दर मंजूर कर ली गयी हैं। लेकिन कुछ मोटी मोटी आपत्तियां ऐसी थीं कि जिन पर पुनः विचार किया गया और विचार करने के पश्चात् इस बिल में वह संशोधन किए गये। मैं जनाब का ध्यान उन संशोधनों की तरफ़ दिलाना चाहता हूं क्योंकि अगर उनको विचार में रखा जाए तो बहुत सी आपत्तियां जो इस बार फिर की गयी हैं वह उसमें से हट जाती हैं।

जो बिल शुरू में रखा गया था उसमें सेक्शन ५ में यह प्रावीजन था कि इस कानून के लागू होने के समय जिस किसी किसान पर ३० एकड़ से ज्यादा जमीन हो वह जो ३० एकड़ जमीन रखना चाहता है उसका और जो जमीन उसके पास ३० एकड़ से ज्यादा है उसका ब्योरा सरकार को दे। अगर वह ऐसा नहीं करता तो इल्जाम गिना जाता। प्रवर समिति ने इस चीज को मुनासिब समझा कि एक ऐसे देश में जहां बहुत से लोग अनपढ़ हैं और उनको क़ानून के बारे में जानकारी नहीं होती, इस तरह के प्रावीजन को न रखा जाए, क्योंकि उसके रखने से उनको नुक़सान पहुंच सकता है, जो कि मुनासिब नहीं है। प्रवर समिति ने मुनासिब समझा कि यह ब्योरा तैयार करने की जिम्मेदारी किसान पर न डाली जाए बल्कि एक मियाद के अन्दर अन्दर सरकार अपनी मैशिनरी से या अपने अफ़सरों की मदद से यह ब्योरा तैयार कराए। यह एक बहुत बड़ी बात है। अगर कोई किसान मियाद के अन्दर अन्दर सरकार के रोबरू यह ब्योरा नहीं रखता तो सरकार अपनी मैशिनरी के जरिए उस ब्योरे को तैयार कराए, इसकी जिम्मेदारी सरकार पर डाली गयी है। इसलिए अब सेक्शन ५ में रखी गई धारा इस प्रकार है। मैं उसको पढ़कर सुनाता हूं :

"If any person who, under section 4 is required to submit a return fails to do so in accordance with the provisions of that

section, the competent authority shall collect the necessary information through such agency as may be prescribed."

ओरिजिनल बिल में यह "शैल" शब्द नहीं था बल्कि सारी जिम्मेदारी किसान पर थी। इसके अन्दर यह इम्प्रूवमेंट किया गया है।

दूसरा क्लाज़ नम्बर ६ है। ओरिजिनल बिल में यह था कि एक फ़ैहरिस्त सरकार तैयार कर ले और उसकी इशाअत कर दे और उस मियाद के बीच यानी तीस दिन के अन्दर अन्दर अगर किसी शख्स को कोई आबजेक्शन करना हो तो कर सकता है और तीस दिन के बाद वह बात बिल्कुल बन्द हो जाएगी, अगर उस मियाद के बाद कोई किसी किस्म का आबजेक्शन करना चाहेगा तो उसकी कहीं सुनावाई नहीं हो सकेगी। यह भी एक बहुत सख्त धारा थी। हमारे मुल्क में ऐसे हालात हैं कि जिन लोगों पर यह कानून लागू होता है वह ज्यादातर क़ानून को नहीं समझते हैं, इसलिए अब सेक्शन ६ में यह सुधार किया गया है कि मियाद के बाद भी अगर कमिश्नर चाहे तो इस किस्म के आबजेक्शन को मंजूर कर सकता है ताकि अगर किसी आदमी को नुक़सान होता हो तो वह उससे बच जाए।

इसके बाद कम्पेन्सेशन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। मैं पहले भी कह चुका हूं और फिर भी दुहराना चाहता हूं ....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बहुत तफसील में कह रहे हैं, पर वक्त बहुत ज्यादा नहीं है।

श्री राधा रमण : मुझे पांच मिनट दीजिये, मैं इतने वक्त में खत्म कर दूंगा।

जहां तक कम्पेन्सेशन का ताल्लुक है इस में अब यह संशोधन किया गया है कि रेवेन्यू का चालीस गुना कम्पेन्सेशन दिया जायेगा। पहले स्लैब सिस्टम था, अब उसको हटा कर फ्लैट सिस्टम कर दिया गया है। यह सुधार क्लाज १० में किया गया है। जहां तक इस कम्पेन्सेशन का सवाल है, मैंने पहले भी कहा था और फिर कहना चाहता हूं कि यद्यपि यह हमारी सरकार की नीति है कि वह आम गरीब लोगों को आराम पहुंचाना चाहती है, उनकी मिल्कियत को बढ़ाना चाहती है, उनके स्टेंडर्ड को बढ़ाना चाहती है, लेकिन जब कृषक लोगों की जमीन लेने का सवाल आता है तो उनको जो कम्पेन्सेशन दिया जाता है वह मारकेट वेल्यू से हजारों गुना कम होता है। अगर उसको इस दफ़ा के मुताबिक रेवेन्यू का ४० गुना मुआवजा दिया गया तो एवेरेज में उसको एक एकड़ जमीन का १००-१५० रुपया मिलेगा और यह इतना कम है कि जो वह इस जमीन से कमाता था और अपने बाल बच्चों का पेट पालता था और कुछ स्टेंडर्ड कायम किये हुए था वह सारा खत्म हो जायगा। फिर यह भी पता नहीं कि इस तरह से जो जमीन सरकार लेगी वह भूमिहीनों को दी जायेगी। उसका क्या होगा पता नहीं। जब ऐसी हालत हो तो कम्पेन्सेशन ऐसा होना चाहिए कि जिसे सबस्टेंशियल कहा जा सके। इस में जो सुधार किया गया है कि पहले जो स्लैब सिस्टम था उसकी जगह फ्लैट सिस्टम कर दिया गया है, पहले यह था कि दस गुना, बीस गुना, तीस गुना या ४० गुना मिल सकता था, अब सब को चालीस गुना मिलेगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर फिर विचार करे और ऐसा कम्पेन्सेशन दे ताकि किसान को यह ख़याल न हो कि उसकी जो जमीन सरकार ले रही है वह कौड़ियों में ले रही है और उससे लाखों और हजारों रुपये का फायदा उठायगी। एक तरफ आप किसानों को नुक्सान पहुंचा कर उनकी जमीन ले रहे हैं दूसरी तरफ उसको गरीबों को भी नहीं दे रहे हैं जिससे उनको फायदा पहुंचता हो और वह जमीन किसानों के ही पास

[श्री राधा रमण]

रहती हो । इसलिए इस पर पुनः विचार करने के लिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा ।

कम्पेन्सेशन के सिलसिले में एक बात यह हुई है कि जिन लोगों के पास बहुत थोड़ी जमीन है, उन को बांड की शक्ल में कम्पेन्सेशन देने के बजाये कैश में देने का इरादा किया गया है । मैं समझता हूं कि यह एक वैलकम बात है और मैं इस का स्वागत करता हूं । चूंकि दिल्ली में ऐसे किसान गिनती के होंगे, जिन की जमीनें गवर्नमेंट ले सकेगी, इसलिए मैं यह चाहता था कि बजाये इस के कि उन को बांड्ज़ की शक्ल में कम्पेन्सेशन दिया जाये और उन को कीमतें भी आधी चौथाई मिलें, जिस की वजह से उन को नुकसान हो और फायदा न हो फौरन न मिल सके, बेहतर यह है कि उन सब की पूरी कीमतें अदा कर दी जायें । अगर वह नहीं हो सकता है, तो जो शक्ल रखी गई है, वह उस से कुछ बेहतर है ।

एक बात इम्प्रूवमेंट की यह की गई है कि पहले यह व्यवस्था थी कि जिस किसान के पास आठ एकड़ जमीन थी, अगर वह चाहता कि उस में से दो, चार, छः एकड़ जमीन किसी रिलीजस परपज के लिए, या भूदान के लिए, या किसी अच्छे काम के लिए किसी लैंडलैस पैज़ेन्ट को दे दे, तो उस को ऐसा करने का अख्तियार नहीं था, लेकिन अब प्रवर समिति ने इस संशोधन को मंजूर कर लिया है कि जिन किसानों के पास आठ एकड़ जमीन है, वे उस को बेच तो नहीं सकेंगे, लेकिन गिफ्ट के तौर पर दो, चार, छः एकड़ जमीन किसी रिलीजस परपज के लिए, या भूदान के लिए या किसी सवाब के काम के लिए दे सकेंगे ।

ये चन्द बातें इस बिल में इम्प्रूवमेंट की हुई हैं । मैं समझता हूं कि इस से बिल की शक्ल पहले से अच्छी हो गई है ।

कुछ लोगों ने इस बात पर आपत्ति की है कि जहां किसानों की जमीनों को हम हासिल करते हैं, एक्वायर करते हैं और उन की सीलिंग मुकर्रर करते हैं, वहां नान-एग्रीकल्चरल प्रापर्टी के ऊपर कोई सीलिंग मुकर्रर नहीं की गई है । मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं और अब दोहराना चाहता हूं कि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि हल्के हल्के नान-एग्रीकल्चरल प्रापर्टी पर भी सीलिंग लगाना जरूरी होगा । सरकार इस सिलसिले में इस वक्त तक जो कदम उठा सकी है, उन में नान-एग्रीकल्चरल लैंड पर कुछ कायदे-कानून या कुछ नये तरीके अख्तियार किये गये हैं, जिन से उस को कम किया जा सके । लेकिन वे नाकाफ़ी हैं । मैं सरकार से यही उम्मीद करूंगा कि जनता की इस मांग पर भी ध्यान दिया जायगा और अरबन प्रापर्टी पर भी कोई न कोई सीलिंग लगाई जायगी और वह जितनी जल्दी होगा, मुनासिब होगा ।

मैं यह अर्ज करूंगा कि प्रवर समिति से वापस आने के बाद भी यह बिल मुकम्मल नहीं है और इस बारे में बहुत पेचीदगियां पैदा होंगी, लेकिन जबहम ने सारे देश के लिए इस सिद्धान्त को मन्जूर किया है कि लैंड की एक सीलिंग मुकर्रर की जाय, तो उस सिद्धान्त को दिल्ली में भी लागू करना जरूरी है—और दिल्ली के लिए हम ने तीस स्टैंडर्ड एकड़ की सीलिंग मुकर्रर करना मुनासिब समझा है—चाहे उस से कितनी ही कम जमीन क्यों न मिले । बहुत से लोग कहते हैं कि दिल्ली में इस कानून के लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि यहां पर ऐसे किसानों की तादाद बहुत कम है, जिन के पास तीस एकड़ से ज्यादा जमीन है और उन के पास जो जमीन है, वह इतनी नहीं है कि जब यह कानून लागू होगा, तो हम बहुत जमीन पा सकेंगे । जब हम ने यह सिद्धान्त माना है और दूसरे प्रान्तों में इस को मन्जूर

किया गया है, तो लाजिमी तौर पर यहां राजधानी में भी यह लागू होना चाहिए। यहां पर जो लेजिस्लेचर थी। दिल्ली में जब लोकप्रिय हुकूमत थी, उस ने भी यह ख्याल जाहिर किया था। इस समय यहां के लोगों की तरफ़ से एसी कोई आपत्ति हो, यह मैं मुनासिब नहीं समझता।

इसलिए प्रवर समिति से आयु हुए इस संशोधनात्मक विधेयक का मैं स्वागत करता हूं और जो आपत्तियां इस बारे में प्रकट की गई हैं, वे इस नजरिय की गई हैं कि इस बिल को ज्यादा से ज्यादा मुकम्मल और लाभदायक बनाया जाय। मैं आशा करता हूं कि सारा हाउस इस को कुबूल करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी और मेम्बर साहबान को बुलाने से पहले मैं यह कह देना चाहता हूं कि हम पहले से ही बहुत टाइम ले चुके हैं। दो बजे मैं मिनिस्टर साहब को जवाब देने के लिए दरख्वास्त करूंगा। दस मेम्बर पहले बोल चुके हैं। अब जो मेम्बर साहबान बोलें, वे दस मिनट में ही अपने ख्यालात रख दें।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रवर समिति से इस बात की बहुत आशा थी कि वह दिल्ली भूमि अधिकतम सीमा बिल पर अच्छी तरह सोच-विचार करेगी और जितनी भी धाराओं में संशोधन करने की आवश्यकता है, उन के बारे में सदन के सामने अपनी तजवीजें पेश करेगी। पंडित ठाकुर दास भार्गव और दूसरे साथियों ने यह ख्याल जाहिर करने की कोशिश की थी कि हम उसूली तौर पर सीलिंग के खिलाफ़ नहीं हैं, सीलिंग तो लगे, लेकिन सीलिंग के आगे जो कार्यवाही है, वह न्याय की रीति से ही की जाय और उस में किसी के साथ ज्यादती न हो। इस के ऊपर यहां पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। हमारे यहां बहुत से साथी हैं, जिन का ख्याल है कि हम दिल्ली के साथ मिल जायें, लेकिन जिस वक्त हम ऐसी बातें देखते हैं और ऐसे बिल हमारे सामने आते हैं, तो हमें एक डर सा लगता है दिल्ली के साथ जुड़ने में, क्योंकि यहां पर जो भाई विचार करते हैं, उन के दिल में जमीन की वह कीमत नहीं होती है, जो पंजाब के किसी काश्तकार के दिल में होती है।

इस बिल में कम्पेन्सेशन के बारे में जो धारा १० है, मैं उस के खण्ड २ और ३ की तरफ़ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप जानते ही हैं कि जमीन तो जरिया-ए-पैदावार है और कारखाने भी जरिया-ए-पैदावार हैं और मकान तो सिर्फ़ रहने की सहूलियत है। इस बिल में हम ने यह माना है कि मकान की कीमत तो जरूर बाजार भाव के हिसाब से मिलनी चाहिए, लेकिन जमीन की कीमत बाजार भाव के नजदीक भी न हो। मेरे भाई ने कहा कि वह डेढ़ दो सौ रुपये बैठता है। शायद उन को पता नहीं—क्योंकि उन्होंने कभी माल दिया नहीं—कि वह मुश्किल से चालीस पचास रुपये एकड़ के हिसाब से बैठता है। दिल्ली में बाजार भाव एक एकड़ का पांच हजार रुपया हो और उस का मुआवजा हम पचास रुपया दें, यह कहां का न्याय है? हम कहते हैं कि सोशल रिफ़ार्म के लिए समाज के हर एक अंग को कुछ न कुछ कुर्बानी करनी चाहिए। उस में मुझे कोई एतराज नहीं है। इम्पीरियल बैंक के जो हिस्सेदार थे, उन से भी कुर्बानी कराई गई। अगर हिस्से की फ़ेस वैल्यू ही दे दी जाती, तो हमें शिकायत न होती, लेकिन उस से पांच गुना मार्केट वैल्यू के तौर पर उन को मुआवजा दिया गया। लेकिन जो जमीन सोना पैदा करती है, जो अनाज पैदा करती है, उस के मुआवजे के लिए

[चौ० रणबीर सिंह]

जो तरीका अख्तियार किया गया है, उस में कोई न्याय नहीं किया जा रहा है । उस जमीन के ऊपर अगर किसी ने दो हजार रुपये का मकान बना दिया है तो उस की कीमत दो हजार रुपय जरूर मिलेगी, चाहे एक एकड़ जमीन का मुआवजा सिर्फ़ साठ रुपये ही मिले ।

यह समझ में नहीं आता । मैं जानता हूं कि इस देश के अन्दर बहुत सारे भाई हैं और बहुत सारे प्रान्तों से आते हैं । वहां जो जमीन का तरीका है वह पंजाब में कभी नहीं रहा । पंजाब और दिल्ली के आसपास के जो भाई खुशहाल रहे, जो काश्तकार खुशहाल रहे उन की एक ही वजह थी कि दूसरे सूबों में तो सन् १९४७ के बाद जमीन की जो खेती करते थे, मिल्कियत के हकूक यह जमींदारी एबालिशन के बाद मिले लेकिन यहां तो सालहा साल यह हक रहा । बहुत सारे राज्य आये दिल्ली के अन्दर और चले गये लेकिन जो खेती करने वाले थ वह वहीं के वहीं रहे और शान्ति से अपनी खेती करते रहे और खेती करने में वह होशियार थे । अगर यह जमीनें जमींदारी की होतीं तो मुझे कोई एतराज नहीं था क्योंकि उस हालत में शायद यह अंग्रेजों की सेवा करने के लिए या देश के साथ गद्दारी करने के नाते अगर कोई इनाम मिला होता तो मैं तो उससे भी आगे जाता और कहता कि एक कौड़ी भी उनको न दो । लेकिन इन्होंने यह जमीन खरीदी है । यह जमीन उन्होंने कोई जागीरदारी के नाते नहीं ली कोई जमींदारी के नाते नहीं ली बल्कि वह तो एक तरह से पीजेंट प्रापराइटर थे । अब उनके लिए यह जो ३० स्टैन्डर्ड एकड़ की सीमा मुकर्रर की है तो इसको तो किसी हद तक बर्दाश्त भी किया जा सकता है लेकिन उस से यह कहना कि तुम को बाजारी भाव भी नहीं देंगे यह उस के साथ अन्याय है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस में लिखा है कि जो अधिकतम सीमा मुकर्रर करते वक्त पंजाब और उत्तर प्रदेश का और आसपास के सूबों का ख्याल रक्खा गया है तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने पंजाब के कानून में जो मुआविजे की धारा रखी है उस की तरफ भी ध्यान क्यों नहीं दिया है ? वहां उस में लिखा हुआ है कि सीलिंग के बाद जो फालतू जमीन काश्तकारों से ली जायगी उसका मुआविजा जो उस समय बाजारी रेट होगा उसका ७५ फीसदी दिया जायगा । मैं मान सकता था अगर ७५ के बजाय वह ६० फीसदी भी बाजारी रेट का मुआविजा देते । मैं दूसरे ढंग से मानने को तैयार हूं और वह यह कि जिस तरह पंजाब में मरला टैक्स लगाया यहां भी कोई इस तरह का मरला टैक्स लगता । यहां भी शहर बढ़ रहा है और उस के कारण जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं और इसलिए यह मरला टैक्स देना चाहिए लेकिन उस के बाद जो उस का हक पहुंचता है उतना मुआविजा उसको देना चाहिए । लेकिन आज उसके साथ न्याय नहीं हुआ है यह देख कर मुझे बड़ा दुःख होता है । जो जमीन पर अनाज पैदा करे उसके मुआविजे का उसूल दूसरा है । जो भाई मुआविजा मुकर्रर कर रहे हैं ऐसा मालूम होता है कि उन को जमीन से दुश्मनी है, ऐसा मालूम देता है, मकान से प्यार है और जो उस के अन्दर सामान लगाया जाय उस से प्यार है लेकिन जमीन से दुश्मनी है । मैं तो समझता हूं कि इस देश के अन्दर ७० फीसदी आदमी हैं और यह जो जमींदारी एबालिशन हुई उस के बाद कम से कम ५० फीसदी देश की ऐसी आबादी है जिस का कि जमीन की मिल्कियत से एक रिश्ता है और इस तरह जमीन की मिल्कियत के साथ जो हमारा रिश्ता है उस रिश्ते को आज डेमोक्रेटिक जमाने के अन्दर इस तरह से ठेस पहुंचाना, मैं समझता हूं कि यह सही नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके बाद जो छूट दी गई है उस सिलसिले में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। उस के अन्दर लिखा है कि फलां तारीख के अन्दर अगर कोई बगीचा लगा हुआ था तो वह तो छूट सकता था। लेकिन जो उस के बाद अगर बगीचा लगेगा वह नहीं छूट सकेगा। अब मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह कौन से न्याय की बात है? क्या उस तारीख के बाद देश को बगीचों की जरूरत नहीं है? देश के लिए जितने भी फल वगैरह पैदा करने थे वह उस वक्त तक जो बगीचे लगाये जा चुके हैं वह क्या हमारे देश की मांग को पूरा कर सकेंगे? अगर आपके खयाल में वे पूरा कर सकेंगे तब तो मेरी समझ म यह आ सकता है कि फलां तारीख के बाद अगर कोई बगीचा लगाना चाहता है तो उस के साथ कोई रिआयत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हमें फलों के और अधिक पैदा करने की जरूरत है तो जाहिर है कि इस तरह की पाबन्दी नहीं होनी चाहिए।

उसी धारा के अन्दर चीफ कमिश्नर को अधिकार दिया गया है कि जिस चीज के लिए जो छूट दी गई है उसको एक अर्से तक अगर वह पूरा न करे या परा करने में पीछे हट जाय तो वह जमीन उससे वापिस ली जा सकती है। जब हम ने इस धारा के अन्दर ऐसा लिखा हुआ है तो मेरी समझ में नहीं आता कि बगीचे के लिए हम यह फरवरी ५६ और ६० से क्यों प्यार करें। उस के लिए हम को वक्त देना चाहिए। साल, दो साल का वक्त हम दें। अगर उस के भीतर और बाद भी कोई बगीचा लगा सके तो उसको लगाने का मौका दिया जाय ताकि वह देश की सेवा कर सके। मेरे साथी श्री सिंहासन सिंह बहुत उतावले हैं। उनके दिल म एक भावना है और उस भावना की वजह है। मुझे उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में बिड़ला साहब की २० हजार एकड़ जमीन है और उसके अन्दर बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, सामान और मकानात लगाये हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार पर दबाव दिया जाता है कि उसको भी छूट के अन्दर दिया जाय क्योंकि जैसा कि इसमें भी दर्ज है कि अगर जमीन के ऊपर ज्यादा इनवैस्टमेंट की है तो उसको छूट होनी चाहिये। अब उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके लिये यहां तक तैयार हूं कि १००, १५० या २०० एकड़ में जो एक आदमी आसानी से इतने में मिकैनाइज्ड फार्मिंग कर सकता है, उसको यह छूट मिल जाय और यह छूट उसके लिये होनी चाहिये। अब मेरे साथी श्री सिंहासन सिंह का चूंकि मिकैनाइज्ड खेती से कभी कोई खास वास्ता नहीं रहा इसलिये उनके दृष्टिकोण में और मेरे दृष्टिकोण में थोड़ा सा अन्तर है। मैं समझता हूं कि जो एफिशिएंट फारमर है और जो इतनी अधिक पैदावार कर सकता है उसके लिये कुछ तो रिआयत अवश्य होनी चाहिये। लेकिन वह रिआयत इतनी अधिक नहीं होनी चाहिये कि उसके अन्दर कोई बिड़ला या टाटा पैदा हो सकें। हां रिआयत इतनी जरूर होनी चाहिये कि जो भाई मशीन से खेती करते हैं और जिसके कि लिये १००, १५० या २०० एकड़ कोई ज्यादा जमीन नहीं है वह अच्छे ढंग से ज्यादा पैदावार कर सकें और देश में अन्न का उत्पादन बढ़ सकें।

13 hrs.

अब सूरतगढ़ का फार्म मैंने देखा। वहां पर डेढ़ करोड़ रुपया लगा है। ७५० रुपया फी एकड़ वहां पर इनवैस्टमेंट है। एक फसल के लिये २२५ रुपया फी एकड़ के हिसाब से वर्किंग कैपिटल लगता है लेकिन उसके बावजूद भी वहां कभी तो २० मन पैदा किया जाता है और कभी १२ मन और वहां जो यू० पी० के तराई के अफसर थे उन्होंने बतलाया कि सरकार का हिसाब लगाने का तरीका और होता है और आपकी तरह से वहां पर हिसाब नहीं रक्खा जाता। जितनी धरती बोई वह सारी बोई हुई मानी जाय और उसके ऊपर एव्रैज निकाला जाय, ऐसा हिसाब नहीं है। वहां तो यों हिसाब है कि जिसकी एक खास परसेंटेज तक पैदावार न हो उसको उस के

[चौ० रणवीर सिंह]

काट दिया जाता है। मान लीजिये कि ३,००० एकड़ जमीन बोई, ५०० एकड़ भूमि के अन्दर फसल मामूली लगी तो उसको उसमें से काट कर २५०० एकड़ के ऊपर एवरेज निकाला जाता है। अब वहीं तराई के इलाके में जो पंजाब के किसान गये हैं, और खेतीबाड़ी करते हैं और अगर उनकी एवरेज पैदावार सूरतगढ़ के फार्म से ज्यादा है तो मैं समझता हूं कि उनके साथ रिआयत करने का केस बनता है लेकिन बिड़ला और टाटा के साथ यह रियायत नहीं होनी चाहिये।

Shri Rami Reddy (Cuddapah): Mr. Deputy-Speaker, Sir, though this Bill relates to the Delhi territory, Delhi is a centrally administered area and therefore this ought to be a model Bill. The whole country is going to treat this as a model Bill, and therefore, this Bill has to be examined with very great care and with very serious consideration.

The first point which I want to mention is with respect to ceilings. I think the previous speaker also referred to this matter but I could not follow his speech made in Hindi. However, what I am going to say is, I think, the same that he pointed out. I do not know as to why the Government is rushing to fix ceilings only in respect of rural properly and that too only with respect to land. There has been a cry in the country for so many years that a ceiling on both rural and urban property should be fixed. But the Government has not so far taken any steps. There do not even seem to be any proposals for bringing forward any legislation for fixing a ceiling on urban property. That is my first point with regard to this Bill. This Bill is going to affect the land and the rural economy of the country as a whole. Therefore, I want an answer from the Minister whether they are contemplating any legislation for bringing forward and putting a ceiling or fixing a ceiling in respect of urban property.

Then I come to compensation. While the former Imperial Bank was nationalised, the market rate of the shares was paid to the shareholders. But here in this Bill only 40 times the land revenue is proposed to be paid. I do not know why this discrimination is made in respect of the rural property alone. Under section 10 of the Bill, the market rate is proposed to be paid in respect of rural property, such as buildings and some other items. In respect of land alone they have made a special exception, namely, that it will be only 40 times the land revenue. I also want to know why they have made a special discrimination in respect of compensation only on land and not other properties. It is probably because other properties are situated or located in urban areas and therefore they expect much noise from the urban people on this matter. In future if Government propose to bring forward any legislation in regard to ceilings on urban property, probably they expect or contemplate some cry and noise from the urban people, and so, the Government have here itself indicated that they are going to pay the market price to urban property like buildings and other things, in urban areas. Therefore, I want a clarification in respect of this point also.

Now, I come to the mode of payment of this compensation. I understand that there are only 33 or 34 persons coming under the present provisions of the Bill. Therefore, I do not know why there should be a provision that compensation can be paid either in cash or in instalment or in a lump sum or in bonds. As only 33 or 34 persons are affected, I believe that compensation can be paid in cash in full immediately.

Then I should like to refer to the excess land that is going to be handed

over. As I said, this Bill is going to be a model for the whole country and it has been the accepted policy to encourage the co-operatives. I suggest that excess lands should be handed over to the panchayats who might be encouraged to cultivate these lands by forming cooperative societies so that the accepted policy of the Government may be implemented at the Centre in the initial stage itself.

As regards the competent authority, several powers have been given to the so-called competent authority described under the Act. I think the powers are so great that they are liable to be used even excessively, and there is scope for them to indulge in favouritism and nepotism. Therefore, I plead that some care should be taken in regard to this provision also.

Shri Jhunjhunwala (Bhagalpur): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I have no other point to dwell upon except that of compensation. When I was going through the Bill, I found one thing, and I was wondering why a distinction was sought to be made between one kind of land and buildings and the agricultural lands and the trees and so on. I could not understand why such a differential treatment should be meted out to the class which has been the backbone of our country and which has produced so much food, etc. Now, when we are going to acquire their land, we are giving them only a nominal compensation which. as a matter of fact, means nothing to them. It is better to say that they will not get any compensation. It is a sort of confiscation, in my opinion, to pay such a compensation and acquire their land. I would suggest to the Home Minister to look to this point and see that not less than the market value is given to each landholder.

Further, the mode of payment of compensation is very faulty.

13.10 hrs.

[PANDIT THAKUR DAS BHARGAVA *in the Chair*]

A poor man to whom compensation will be given will have to spend at least half of the amount in getting that compensation from the authorities. I am giving my own experience. I had a very small land yielding about Rs. 500 per year and some compensation was allowed. But more than three-fourth of that amount was spent by me in sending my man from here to there and from there to here. I could bear it, it was so annoying. But a poor cultivator may not be able to bear it. If you are giving him compensation by such a method that he has to pay half of it before he gets anything, in spite of getting compensation, he will have to undergo so much troubles and he will not get anything. Therefore, I request the hon. Minister to look into these two things.

There should not be any discrimination between one kind of land and anoher kind of land. He said where more money has been spent on a particular land, that man should get more compensation. Why? If the land is better, the market value of that land will be more. So, he should get compensation at the market rate. In the case of land of people who have not been able to get so much money in order to improve the land, the market value of that land will be less. So, the only principle which should be applied is the market value and before the land is acquired, they should get the compensation.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): Sir, I welcome this Bill most wholeheartedly. On the floor of this House, I have seen many Bills and I have taken part in the discussion with regard to several Bills. So far as this Bill is concerned, I say with due sense of responsibility that it is a masterpiece of ineffectiveness. I do not think it is going to help the cultivators; I do not think it is going to help the landless labourers; I do not think it is going to help those persons who have some land to dispose of. I feel that this Bill is full

[Shri D. C. Sharma]

of so many qualifications, so many exemptions and so many 'buts' and 'ifs' that in actual operation, things will remain very much as they were before.

I was suprised to find some hon. Members expressing apprehensions about the agriculturists and other persons. I can tell them that so far as the working of this Bill is concerned, they need not have any misgivings. This Bill is not going to be a Bill for the dislocation of any interests and so, they can rest in peace. The first thing which strikes me in this Bill is its geopraghical limitation. I should have thought that the Bill should apply to the whole of Delhi. Delhi is not a very big State; it is only a Union Territory and very small compared to other States. But the Bill has been drafted in such a way that the field where this Bill is going to be implemented is going to be very limited. Under clause 1(2), all those areas included in a municipality or in a notified area have been exempted; areas owned by Central Government have been exempted; areas occupied for a public purpose or for a work of public utility have been exempted. In this Bill exemptions are much more important than what is going to be operative. They say, the exception proves the rule. But here the exceptions are so many that there will be no rule. So, this Bill is going to defeat the very purpose for which it is intended.

It has been said that the family will consist of such and members. I do not want to quarrel with the definition of 'family'. Though this definition may be applicable in western countries, it cannot be applicable in Inda. Here we have a different conception of family from what is given here in the Bill. It would have been more appropriate to give a definition of a family which is in conformity to Indian conditions and Indian traditions. That has not been done. All the same, I find again that something has been done, so that the person who has got land can hold the land. Ch. Ranbir Singh is worried over nothing.

It is said here:

> "Provided that where the number of members of the family of such person exceeds five, he may hold five additional standard acres for each member in excess of five, so however, as not to exceed sixty standard acres in the aggregate."

So, the provision is that a man can hold up to 60 acres. I have yet to see many families in India with only five members. Most of the families in India consist of more than 5 members. So, there is ample provision for the people not to part with the land even under clause 3.

In clause 26, exemptions have been given in such bundles and on such a big scale that I think there will be hardly anybody who will part with his land. For instance, if you have built an orchard, your land can be exempted. If you have got land in which you have made a heavy investment, that can be exempted. If you have some land for cattle-breeding, that can be exempted. Any land which is held by a co-operative society can be exempted. So, I think in this Bill, the exemptions outturn the other provisions. I think the drafting of the Bill has been done in such a way that there should be the least dislocation. It is a face-saving Bill. Government is committed to the policy of ceiling on land and they want to say that they are going to provide ceiling for land. So, they are bringing forward this Bill, though this ceiling for land is not going to work in any way very effectively.

Much has been said about compensation.

चौ० रणबीर सिंह : शर्मा जी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की तनख्वाह की सीलिंग के बारे में क्या कहना चाहते हैं ?

Shri D. C. Sharma: I agree with what Ch. Ranbir Singh has said, in spite of what he says, that we cannot have one rule to govern property in the villages and another rule to govern property in the cities. It is against equity.

An Hon. Member: What about the income?

Shri D. C. Sharma: It is against social justice; it is against the principles for which our country stands. I agree with him. But I would say that the compensation which has been provided to these persons, forty times the land revenue in respect of the excess land is, by any computation, by any standard, by any law that is in force at present, absolutely inadequate. I do not want to go into the question of market value, which has ruined our country in many ways. Because, the moment you take the market value there is speculation; the moment you take this, there is a racket. So, I do not want you to take the market value. I feel that those persons from whom you are taking land—I hope they will not be many; they will be very few; perhaps none—we should give them compensation which is equitable. I do not think you can put land on par with a building. Therefore, when they say that they should have the market value I would say that the scheme of compensation should be revised so that the person who is going to part with his land will not suffer.

Then, it has been stated in the Bill:

> "For the purpose of determining the excess land under this section, any land transferred at any time during the period between the 10th day of February, 1959, and the commencement of this Act shall, notwithstanding such transfer, be deemed to be held by the transferor."

A very fine provision. We go on talking about the legislation for some ten years. After ten years we bring a legislation to put it into a little effect. Then that legislation takes about six months in passing. It takes another three months for the legislation to become effective. We have been talking about land ceiling all these years. We have been talking of taking away the land from people, of course after paying them compensation, all these years, and to say that the land which has been transferred between 10th February 1959 to this day will not be valid is to say something which does not have any meaning. People are very wise and they know what the Government is going to do. They know what the Bill is going to be. They know all these things and, therefore, I think the transfers of land which had to be made had already been made. They were made much before the 10th February. Therefore, I think that this clause also is going to be entirely inoperative.

Then, the competent authority has been given some powers. Of course, there is provision for revision and all that kind of thing but, all the same I think the powers given to the competent authority are far in excess of the powers which are held by judicial or revenue or magisterial authority. I do not know what new kind of officer we are going to create for the purpose of this Bill.

There are some persons who are feeling very unhappy about this Bill. I can say to them only this much that, though this Bill has so many clauses, though this Bill has gone to the Joint Committee, though this Bill has been under all kind of scrutiny, it is not going to produce even one-hundredth part of that result which the Government is aiming at. Therefore, the fears of my friends like Ch. Ranbir Singh, who think that they have a monopoly of land interest and that they are the only persons who can talk about land, those fears

[Shri D. C. Sharma]

are entirely unjustified because, as I said in the beginning, I fear that this Bill will keep things as they are, and this is a Bill which ensures the *status quo*.

Shri Tyagi (Dehra Dun): I understand from the speech which the hon. Deputy Minister delivered on the first day that this Bill is basically meant to serve as a model Act for other States to follow. If that is so, then the Bill immediately acquires greater importance than the other Bills which we are usually accusomed to pass in this House.

If this Bill were to serve as a model for other States I feel that the opinions of the State Governments should better have been elicited to know what they feel about it. I wonder whether their reactions had been had and, if so, the House should be given an opportunity to peep into the comments of various States on this subject, because after all, the model legislation for the whole of India must be framed only after the representative opinion of India has been consulted. If there is any such lacuna I would suggest to the hon. Minister to circulate it to the various State Governments at least at this late stage, as it is better to have their views with us before we frame a legislation affecting them. Otherwise, the members of the various State legislatures will criticise the Parliament's wisdom on important matters like this.

Another point on which I feel very strongly is the question of ceiling. So long as I am receiving a pay of Rs. 400 per month from the Exchequer and an allowance of Rs. 21 per day for the working days, so long as the hon. Minister and his colleagues, including the Prime Minister, are receiving a pay of Rs. 2000 or Rs. 3000 per month, so long as the members of the Planning Commission are receiving fat salaries, it does not behove us to say and it is very wrong for us to say that a villager, a person in the village running an agricultural farm, or working in the fields, should get an income of only Rs. 300 and that his fate should be sealed with that. If at all there is a ceiling, let it be Rs. 2,500 or Rs. 3,000, which is the pay of a Central Minister. If a ceiling is fixed at that level, nobody will take objection. But if we put a ceiling of Rs. 300 per month on the villagers, actually the Parliament in its wisdom is giving a verdict that "thou shalt not send thy children to any college or school in a city", because no agriculturist can afford to send his children to a city school if his income is limited to Rs. 300 a month. Do I take it that you want them to continue as agriculturists for all time to come and that they cannot take to any other avocation? Now there are hundreds of thousands of boys who have obtained education and, in some cases, even foreign training. Now if you put a ceiling of Rs. 300 then they would never be able to send their children to schools and their fate would be sealed. Is it your intention that their fate should be sealed because they are born in an agricultural family? It actually amounts to discrimination, and I do not feel morally strong enough to support such a sort of ceiling.

The better thing for the Government would have been to make a proposal that the ceiling would be applied prospectively and that it will not affect the existing landholders. Now each family has four or five members and, according to the Mitakshara rule every child born in the family becomes a partner in the family holding. So, if there are five members in a family in the next generation the share of one member will be only 1|25th part of the existing land. Therefore, my fear is that if this were to be allowed to continue our holdings will become uneconomic.

I, therefore, agree with Sant Vinobha Bhave that in the matter of

agriculture the more important thing is to fix the floor ceiling, that the holding should not be allowed to go below such and such acres. That would be a better way, a prospective ceiling, without any need for paying any compensation from the Exchequer. In that case, within 10-12 years the same ceiling would be achieved in the natural course without paying any compensation to anybody. That would have been a better course. But the Government now have, in their wisdom, thought fit to seal the fate of the agriculturists this way. They can please themselves, but I suggest that they should consult the State Governments also because, strictly speaking, it is they who have to do the needful. In fact, the reaction of the villagers to this measure will be better appreciated by the Governments at the States than by us at the Centre. Our responsibility is rather vicarious. The actual responsibility falls on the shoulders of those people for whom we are proposing this model Act. The State Governments are a better authority to decide the fate about agriculture than us.

But it seems that the Planning Commission has become supreme and it has taken the intelligence and the wisdom of the whole country and it has decided the fate of the agriculturists.

I want to emphasize one more point. They have decided that 60 acres shall be the ceiling for a family, irrespective of the fact how many sons a father have. A father may be eighty years of age and, unfortunately, he may be still alive. If only he had died two months or a year before, his children, five brothers, they will have their land quite secure with them. But unfortunately for them the father has survived for one or two years more to die during this period, that is, after Shri Datar came in the field. So, the sons lose their fate. It is something which looks rather illogical. The families which shed the father about two years back are well-off. For them there is no ceiling. But because the father is alive and he has five children in another neighbouring villager's family, that family will have to suffer on this account. I suggest that this may again be considered.

I do not want to take more time but about compensation again I would like to say that 40 times is really too little. What do we mean by it? Do we want to make the villagers realise that we are not appreciative of his needs and that we have no sympathy with a villager and his property? It is better that land rather than compensation is given. It would be better if land were acquired according to the Land Acquisition Act because then that man will get many times more than what we are giving in ceiling under this law. So it would be better if the excess land, whatever my hon. friend thought was extra could be acquired according to the Land Acquisition Act and taken over by Government. In that case they will get many times more than what is proposed to be given.

Mr. Chairman: The hon. Member's time is up.

Shri Tyagi: I will finsh.

My only point is that after all a villager is my voter. I have to speak for him. I am his representative. If things go without his case being represented here, he will feel that he has been neglected. Therefore, I think it is my duty to say and emphasise that it is the right of the villager. If his land is being taken away, for God's sake give him equitable compensation. This 40 times is really wrong. It is not honest, I must say. 40 times of whatever be the land revenue is Rs. 40 per acre. It is Rs. 1 lakh per acre here on this side because it happens to be in the municipal area. It is Rs. 1 lakh per acre. If you acquire land, you will give Rs. 1 lakh or Rs. 80,000 or so per acre because he is your urban cousin. The other man seems to be a long distant relation. Because the rural area man

[Shri Tyagi]

does not come in contact with us, his land will also cost less. That does not look fair. I very strongly feel about it. If land is being taken, which is enough wound that you are causing him, let him at least be compensated to the extent to which his land is actually costing today in the market. I support the sentiments expressed by my hon. friends. There is no logic also behind this proposal. Therefore I suggest that the hon. Minister might again consider, if he could, this compensation business and see whether instead of 40 times it could be according to the market rates.

Shri Dasaratha Deb (Tripura): Mr. Chairman, Sir, I only want to make three points regarding this Delhi Land Holdings (Ceiling) Bill. One is regarding the ceiling which has been fixed as 30 standard acres under this Bill. Many of my hon. friends have objected regarding having ceiling on land only. But I am for ceilings. I also consider this 30 standard acres ceiling a bit high because in the Union territory of Delhi I do not think that a large amount of excess land would be available. Even in regard to places like Manipur and Tripura the Joint Committee have decided to fix the ceiling as 25 standard acres. I think in these two Union territories more land may be available than in Delhi. But that does not mean that there are not landless people in Delhi. There are so many landless people who are waiting for land to be given. If you accept this ceiling, I am afraid that excess land may not be available for distribution among the landless and poor agricultural workers. So, I suggest that the ceiling should not exceed 25 standard acres.

My second point is regarding certain exemptions made in regard to excess land which may not come under the purview of this ceiling. Here, in clause 18, it is said:—

> "....excess land, if such excess is due to any improvements effected in the land by the efforts of the family or to a decrease in the number of its members."

I can understand the provision, namely, if such excess land is caused due to a decrease in the number of its members, but I do not accept this proposition, namely, if any land is increased due to improvement made by the members of the family. In that case there will be no ceiling. There would not be any ceiling at all because every member of the family can increase its land by reclaiming more land like that and it exceeds the ceiling limit. If you keep the latter portion, that is, excess land caused due to a decrease in the number of its members, it would be all right. But land in which improvements are effected by the members of that family should come under the ceiling limit. It should not be exempted and that provision should not be there.

My third point is regarding distribution of excess land. This Bill does not provide for any priority for distribution of the land after that land comes in the hands of the Government. Who will get priority for getting that land? That provision is not there. I emphatically say that there should be some such provision. Here, it only says:

> "on such terms and conditions as he thinks fit".

that is, the Chief Commissioner or the administrator. It is entirely left in the hands of the administrator. I want it to be categorically laid down in the Bill itself. The first priority should be given to the person who would be evicted from the land when this resumption clause comes into operation. Secondly, it must go to the landless and poor people. Then the other categories will come in. By poor people I mean those people who possess less than the basic family holding which has been prescribed in this Bill itself. If we do not provide

for priority here, I am afraid this land will not go to the proper person, who is actually in need of it, and our slogan of land to the tiller would not be fulfilled. If you want to give effect to this famous national slogan of land to the tiller, you must provide for priority in this Bill itself.

13.37 hrs.

श्री च० कृ० नायर : (बाह्य दिल्ली) : सभापति महोदय, यह जो बिल पेश किया गया उसका पेश होना लाजिमी था क्योंकि हमारी हुकूमत ने इस पालिसी पर अपना फैसला कर लिया था कि तमाम हिन्दुस्तान के अन्दर लैंड रिफार्म्स हों, इन्क्लूडिंग सीलिंग । इसी लिये हमने दिल्ली के लिये भी लैंड रिफार्म को पेश किया और सीलिंग का जो इन्स्टालमेंट है उससे हमारे लैंड रिफार्म का काम पूरा हो जाता है । लेकिन इस रिफार्म को जो कि दिल्ली में हो रहा था हमारा माडल बनाने का इरादा था जो कि मैं समझता हूं कि पूरा नहीं हुआ । अगर इसको माडल माना जाय तो इसमें बहुत सी खामियां रह जाती हैं । इसमें कोई शक नहीं है कि कई चीजें इसमें गोल मोल छोड़ दी गई हैं, जिनको हम आगे चल कर डिफाइन कर सकेंगे, लेकिन एक दृष्टि से यह माडल है कि दिल्ली जैसी छोटी जगह में भी हमने लोगों को लैंड रिफार्म्स से वंचित नहीं रक्खा । इस लिये हिन्दुस्तान की कोई स्टेट यह बहाना नहीं ले सकती कि आखिर कोई न कोई स्टेट लैंड रिफार्म्स के एम्ब्रेस से अलग रह गई । हर एक स्टेट के लिये लैंड रिफार्म्स करना लाजिमी हो जाता है ।

पहली जो चीज मैं कहना चाहता हूं वह सीलिंग के बारे में है । मेरी राय में ३० एकड़ की सीलिंग दिल्ली के लिये पर्याप्त है । अगर दिल्ली के लिये ६० एकड़ की बात कही जाय तो यह कुछ अजीब सा मालूम होता है क्योंकि यहां जमीन बहुत थोड़ी है । और जैसा अभी त्यागी जी ने कहा यहां जमीन की कीमत हजारों लाखों रु० तक पहुंच गई है । इस लिये ६० एकड़ की बात कहना अनरिअलिस्टिक होगा । जो ३० एकड़ रक्खी गई है इसे मैं मुनासिब समझता हूं । लेकिन इसमें एक दिक्कत जरूर है, जो कि स्टैंडर्ड एकड़ के बारे में है । इसके बारे में काफी कहा गया है । इस लिये यह जरूर बतलाना चाहिये कि स्टैंडर्ड एकड़ क्या चीज है । अगर सिर्फ ३० एकड़ हो तो हो सकता है कि कई जगह पर उसे कम माना जाय । यहां स्टैंडर्ड एकड़ का मतलब यह माना जाय कि जिस जमीन की ईल्ड रुपये में १६ आना हो वह स्टैंडर्ड एकड़ है तो जिस जमीन की ईल्ड एकड़ में ८ आना है वह अपने आप ६० एकड़ हो जाती है, जिस में ४ आना हो वह १२० एकड़ हो जाती है । अगर कहीं पर १२ आना ईल्ड हो तो वह साढ़े ३७ या ४० एकड़ तक हो सकती है । यह सही है कि स्टैंडर्ड एकड़ कर दिये जाने से ३० एकड़ से काम चल जाता है लेकिन इस स्टैंडर्ड एकड़ की डेफिनेशन रखना बहुत आवश्यक है । यह डेफिनिशन मुझे कहीं पर भी देखने को नहीं मिली ।

दूसरी बात कम्पेन्सेशन के बारे में है । मैं नहीं समझता कि इस हाउस के अन्दर किसी भी व्यक्ति ने इस कम्पेन्सेशन रेट को स्वीकार किया है, अगर किया है तो एक या डेढ़ आदमियों ने किया है ।

श्री त्यागी : बशर्ते वोट भी सब खिलाफ कर दें ।

श्री च० कृ० नायर : इतना कम्पेन्सेशन रखना बहुत गलत बात है । इससे ज्यादा से ज्यादा १२० रु० आ जाता है । दिल्ली में एक एकड़ की लैंड रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा ढाई या तीन रुपया है । तीन रुपये का चालिस गुना १२० रु० हो जाता है । यह जमीदारों के ऊपर एक मखौल सी है । एक एकड़ की आमदनी कम से कम १० मन से लेकर ४० मन तक होती है । अगर १० मन भी आमदनी हो तो आज कल के हिसाब के मुताबिक उसे १५० रु० मिल जाता है, अगर एक साल में एक

[श्री च० कृ० नायर]

फसल हो तो। दिल्ली में तो दो दो, तीन तीन फसलें भी उठाई जाती हैं। इस लिये एक साल की रेवेन्यू के नाम पर कम्पेन्सेशन देकर जमीन लेना सचमुच बहुत बड़े अन्याय की बात है। यह नहीं होना चाहिये। हमेशा हुकूमत की तरफ से यह कह दिया जाता है कि हम चालिस गुना देते हैं। लोग भी कहते हैं कि "अरे चालिस गुना कम्पेन्सेशन दिया जाता है"। यह चीज उनको गलतफहमी में डालती है। लैंड टैक्स अंग्रेजों के जमाने में बिल्कुल बराय नाम रक्खा जाता था। ६ आना बीघा। ६ आ० या ८ आ० बीघा एकड़ में जा कर करीब ढाई रुपया हो जाता है। कोई खास जमीन हो तो वह १० आना हो सकता है। इसी लिये मैंने ३ रु० रक्खा। ३ रु० के हिसाब से चालिस गुना १२० रु० बनता है। यह बात ठीक नहीं है। दिल्ली में आज कल सब जगहों पर कम से कम २ रु० गज कीमत बढ़ गई है। चाहे मथुरा रोड हो, चाहे जी० टी० रोड हो जो गाजियाबाद को जाती है, या नजफगढ़ रोड हो। दिल्ली के बाहर भी जमीन की कीमत कम से कम २ रु० गज बढ़ गई है। २ रु० गज से मतलब है कि अगर ५००० गज भी हो तो कम से कम १०,००० रु० कीमत बढ़ गई। १०,००० रु० से लेकर २०,०००, २५,००० और ५०,००० फी एकड़ तक जमीन की कीमत बढ़ गई है। लेकिन जमींदार को कम्पेन्सेशन के नाम से १२० रु० दिया जाता है। यह बिल्कुल ही नाजायाज चीज है और कानून के या किसी भी इन्साफ के मातहत यह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मुझे खुशी है कि तमाम मेम्बरों ने इसे अपोज किया।

Shri Tyagi: We can't be a party to this.

श्री च० कृ० नायर : चालिस गुने की बात सुन कर हमें धोखे में नहीं आना चाहिये। चालिस गुने की बात ठीक नहीं है।

अब मैं एक्सेस लैंड के बारे में कहना चाहता हूं। जो कुछ मेरे पूर्व वक्ता ने बतलाया मैं उसका क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। पेज ८ पर सेक्शन १३ है :

> "Where a person representing a family holds land not exceeding the ceiling limit, but subsequently the land held exceeds the ceiling limit, then, notwithstanding anything contained in this Chapter, such person shall not be required to surrender any part of the land on the ground that it is excess land,..."

इसके बारे में मैं जरा क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। जब गवर्नमेंट ने जमीन रिफ्यूजियों को दी तो उनसे किराया लिया और उनको १५ रु० महीने में मकान दिया। अब जब टैक्स लगाया जाता है तो उसकी रेंटल वैल्यू रक्खी जाती है ६० रु० महीना। यह कहां का इन्साफ है? मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि राजेन्द्र नगर में एक सिंगल रूम टेनमेंट का किराया गवर्नमेंट की तरफ से १५ रु० था। लेकिन जब कारपोरेशन की तरफ से टैक्स लगाया जाता है तो उसकी रेंटल वैल्यू ६० या ६४ रु० रक्खी जाती है। यह कोई इन्साफ की बात नहीं है। खास कर जो जमींदार है, चूंकि उसकी कोई आवाज नहीं है, इस लिये उसके साथ यह जुल्म नहीं होना चाहिये।

कम्पेन्सेशन के बारे में भी मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा। कम्पेन्सेशन को बान्ड्स की शक्ल में देना बेइन्साफी है। बांड्स की शक्ल में जब दिया जाता है तो गांवों के मालिकों को दिया जाता है। यहां तो शायद इस सीलिंग के कानून की जरूरत भी नहीं थी। शायद ३० या ४० आदमियों पर इसका ऐफैक्ट होता है। लेकिन चूंकि यह देश में आदर्श के रूप में है इस लिये हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि छोटी छोटी जमीन वालों को भी बांड्स की शक्ल में कई सालों में कम्पेन्सेशन दिया जाय। यह उन लोगों की दृष्टि से ठीक नहीं है। इसमें डिस्ट्रिब्यूशन के भी तरीके बतलाये गये हैं। एक तो यह कि

लैंडलेस को दिया जाय, दूसरा यह कि कोम्रापरेटिव्ज को दे दिया जाय और तीसरी बात मैं कहता हूं कि जो अनएकानमिक होल्डिंग्स वाले यानी ८ एकड़ से कम वाले हैं उनको दे दिया जाय। चूंकि यह डिस्ट्रिब्यूशन आसान नहीं है इसलिये इसे कोम्रापरेटिव्ज के लिये ही दे दें तो शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन इसको ऐलाट करने का अधिकार चीफ कमिश्नर को देने से उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी। इसको एक आफिसर पर नहीं छोड़ना चाहिये।

अब मैं गरीब किसानों की एक बात कह कर समाप्त करना चाहता हूं। हमारे ओरिजिनल बिल में यह रक्खा गया है कि ८ एकड़ से कम जमीन जिस के पास होगी वह नहीं बेच सकता। ८ एकड़ को एक किस्म से एकानामिक यूनिट माना गया। ठीक है। लेकिन अगर एक आदमी के पास ४ एकड़ जमीन हो या ३ एकड़ जमीन हो तो वह एक जोड़ी बैल नहीं रख सकता, एक बैल भी नहीं रख सकता, जोड़ी की बात तो छोड़िये। ऐसा आदमी अगर चाहे कि वह एक एकड़ जमीन बेच कर, जिससे कि उसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से ५,००० रु० मिल जायेगा, अपने गुजारे का इन्तजाम करे, तो इसमें क्या गुनाह है? यह क्या बात है कि अगर उसे बेचनी हो तो ८ के ८ एकड़ बेचे। यह उसके साथ एक जुल्म है। यहां पर ७ एकड़, ५ एकड़, ३ एकड़ और २ एकड़ जमीन वाले इस तरह के हैं कि एक या दो एकड़ बेच देने से उनको ५,००० या १०,००० रु० मिल सकते हैं। इससे वह बिजिनेस कर सकते हैं। उनके लिये इसकी सहूलियत होनी चाहिये। मेरा नम्र निवेदन है कि इस पर विचार होना चाहिये।

अब जैसा श्री राधा रमण ने भी कहा है, शहरों पर सीलिंग होनी चाहिये, मैं उनके इस सुझाव का पूरा समर्थन करता हूं।

श्री सिहासन सिंह (गोरखपुर): सभापति महोदय, जैसा कि शर्मा जी ने कहा इस के अन्दर प्रतिवाद इतने हैं कि यह बिल प्रतिवादों से भरा हुआ है और उसका असर कुछ नहीं पड़ने वाला है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी ध्यान दिलाया और साथ ही मैं यह देख रहा हूं कि जब से इस पर चर्चा चली है किसी वक्ता ने भी इस बिल का समर्थन नहीं किया। यह ठीक है कि कांग्रेस ने अपने सेशन में सीलिंग का प्रस्ताव पास किया है और उसका समर्थन भी किया गया है लेकिन जिस रूप में यह बिल आया है उसका समर्थन नहीं है। क्या गवर्नमेंट इस पर ध्यान देगी अगर वाकई में प्रजातांत्रिक राज्य के कुछ मानी हैं। अब जैसा कि भाई त्यागी जी कह रहे थे कि खिलाफ बोलेंगे तो लेकिन वोट उसके समर्थन में करेंगे तो वह तो मजबूरी है और फिर विचार अलग चीज है और वोटिंग अलग है और उसमें पार्टी के अनुशासन का ख्याल आता है . . . . .

श्री त्यागी: भाई हम तो जो कहते हैं वही करते हैं। पार्टी से ज्यादा किसान हम को प्यारा है।

श्री सिहासन सिंह: हम भी वही करते हैं और उम्मीद करता हूं कि सब भी ऐसा ही करें। अब अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की भावना से प्रेरित होकर काम नहीं करती है और जबर्दस्ती करती है और उचित रुख जो कि उसे अपनाना चाहिए नहीं अपनाती है तो फिर इस देश की गाड़ी ठीक से नहीं चल सकती। ऐसे कंट्रोवरशियल बिल के लिए उचित तो यह था कि हम इस पर अलग बैठ कर सोचते और उसके बाद इसको हाउस में लाते लेकिन गवर्नमेंट अपना बिल लाती है और उस पर हम अपने विचार प्रकट करते हैं लेकिन व्हिप हो जाते मजबूर होकर उसके पक्ष में वोट देना पड़ता है और वह पास ही आता है।

मैं इस बिल का विरोध तीन बातों से करना चाहता हूं। एक तो इस बिल के अन्दर ही दो स्वरूप दिये गये, शहरी जमीन के और देहाती जमीन के। इस बिल के

[श्री सिंहासन सिंह]

अन्दर जो पहला क्लाज है उस में यह दिया हुआ है कि ऐसे एरियाज जो कि किसी म्युनिसिपैलिटी में शामिल होंगे, उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। म्युनिसपल ऐरिया वाला चाहे काश्तकार हो, जमींदार हो या कोई भी हो उन पर यह क्लाज लागू नहीं होगा। मैं नहीं जानता कि शहरी आबादी वालों के साथ आपको इतना प्रेम क्यों है। जैसे कि अभी श्री राधा रमण ने कहा कि जिस तरह से देहात वालों की जमीन की और आय की सीलिंग की जा रही है उसी तरह से यह शहर वालों की आमदनी पर भी कोई सीमा क्यों नहीं लगाई जाती। जितनी भी यह सीमा है आमदनी पर वह सब देहात वालों पर ही लागू की जाती है लेकिन शहर वालों को अछूता छोड़ दिया जाता है। मेरी समझ में यह गांव वालों के साथ सरासर नाइंसाफी है। आखिर यह शहर वालों और गांव वालों के बीच में इस सीमा के सम्बन्ध में भेदभाव क्यों बर्ता जाता है? अब हम शहर के अन्दर जमीन रखते हैं और देहात के अन्दर भी जमीन रखते हैं तो शहर की जमीन पर तो कोई सीलिंग नहीं लगाते हैं लेकिन देहाती इलाके की जमीन पर सीलिंग करते हैं। इसलिए मेरी राय में यह जो पहला क्लाज कहता है कि म्युनिसिपल एरिया में जो जमीनें हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होगा, यह बड़ा अनुचित है। कई जगह जमींदारी एबौलीशन हुआ। उत्तर प्रदेश में और अन्यत्र भी जमींदारियां हम ने समाप्त कीं लेकिन मेरा कहना यह है कि शहरों की जमींदारियां समाप्त नहीं हुईं। कानून तो पास हो गया लेकिन वह शहरों पर लागू नहीं हुआ। पता नहीं क्या असर गवर्नमेंट पर शहर वालों का है कि गवर्नमेंट उन पर इस तरह की कोई पाबन्दी नहीं लगाती। अजी लागू करना तो दरकिनार शहर वालों की आमदनी और जमीन पर सीलिंग लगाने के लिए कानून भी पास करने को सरकार तैयार नहीं है।

मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि अब तक गवर्नमेंट ने तीन, चार चीजों पर ध्यान दिया है। एक तो उस ने जमींदारियां एबालिश कीं, जमींदारियां समाप्त कीं और उनका सरकार ने मुआविजा दिया। ऐयर सर्विसेज को नेशनलाइज किया और फिर हमने बीमा कम्पनियों को लिया और उसके बाद हम ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जब हम ने एयर सर्विसेज को अपने हाथ में लिया तो गवर्नमेंट ने उन प्राइवेट सर्विसेज को सड़े गले पुर्जों के दाम भी बाजार भाव पर दिये हैं। इसी तरह आपने बीमा कम्पनियों को जो अपने हाथ में लिया तो जो उनका दस रुपये का शेयर जिसकी कि मार्केट प्राइस १०० हो गयी उसका भी ५ गुना हम ने उन को दिया। उनके दस रुपये के शेयर का हम ने ५ गुना दिया अर्थात् १० का आपने ५०० दिया। इम्पीरियल बैंक को नेशनलाइज किया वहां भी यही किया गया अर्थात् शेयर मार्केट का पांच गुना दिया। शेयर की वैल्यू जो मार्केट में थी उसका हम ने पांच गुना दिया। लेकिन इसी तरह से मुआविजा हम ने काश्तकारों को जो कि जमीन खरीदते हैं, ज्यादातर जमीनें खरीदी हुई हैं, तो जो हमने बयनामे खरीदे, उन पर इस रेट से मुआविजा नहीं दिया। अभी तक लैंड एक्वीजीशन कानून लागू था। उसका मूल आधार यह है कि जो मार्केट वैल्यू हो जो बाजारी कीमत हो उस का १५ गुना गवर्नमेंट और देती है। अगर किसी की जमीन सरकार उस की मर्जी के बगैर ऐक्वायर करती है तो जो उस का बाजारी भाव होता है उस पर १५ गुना और मुआविजा देती है। ब्रिटिश टाइम्स में जो पुराना लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट था उस का खयाल न कर के आप ४० गुना देते हैं

अब मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। मान लीजिये कि मैं जमीन का मालिक हूं।

मैंने किसी जमीन को महाजन को लीज पर दे रक्खा है दस रुपया लीज पर दे रक्खा है । उस पर उस महाजन ने मकान बना लिया है तो वह जमीन अगर सरकार लेती है तो मुझे जोकि जमीन वाला हूं उस को तो अगर उस का ३ रुपया लगान है तो कुल १४० रुपये मिलेंगे जबकि १२० रुपये सालाना हम लीज के उस से पा रहे हैं । उस का भी कोई लिहाज नहीं होगा लेकिन महाजन को जो मकान की कीमत होगी वह दी जायगी । जब उस ने मकान बनवाया था तब उस का वह मकान ४००० रुपये का था लेकिन आज उसी मकान की कीमत ४० हजार हो गई है तो उस को ४० हजार मुआविजा मिलेगा । उस को तो ४००० का ४०००० मिलेगा लेकिन हम को केवल १२० रुपये मिलेंगे । यह क्या अन्याय है ? मौडेल बिल अगर आप बनाना चाहते हैं तो वह न्याय से भरपूर होना चाहिये जिसे कि सब स्वीकार कर सकें ।

मैं अब थोड़ा क्लाज २६ की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । प्लानिंग कमिशन ने जो लैंड सीलिंग के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट निकाली थी उस में किसी तरह का यह प्रबन्ध नहीं किया था कि जमीन छोड़ी जाय । उन्हों ने यह कहा था कि तीन गुने से भी ज्यादा किसी के पास न हो । एक फैमिली होल्डिंग की डेफनीशन उन्हों ने दी थी वन प्लाऊ यूनिट । अगर एक प्लाऊ से १० बीघे जोत सकते हैं तो ३० बीघे से ज्यादा न हो । दूसरा प्लानिंग कमिशन हुआ । मेरा खयाल है कि मैं ने अपनी पार्टी में भी कहा था और यहां भी कहता हूं कि उस पर शहर वालों का, बड़े बड़े पूंजीपतियों का और बड़े बड़े अफसरों का भी जिन्हों ने कि जमीनें ऐक्वायर कर ली हैं, उन का असर पड़ा और उन को छूट मिल गई । दफा २६ में बतला दिया गया है कि इस तरह की जमीन एग्जम्प्ट कर सकते हैं । चीफ कमिशनर को यह छूट देने का अधिकार दिया गया है । चीफ कमिश्नर को इस दफा के द्वारा यह अधिकार दिया गया है कि ऐसी जमीनें जहां कि कैटिल ब्रीडिंग, डेयरी या वूल रेजिंग का काम चलता हो, उन को इस से छूट दे सकता है । हम भले ही जमीन पर चाहे कितना गल्ला क्यों न पैदा करते हों उस को तो इस कानून से छूट नहीं मिलेगी लेकिन अगर कोई दस गाय वहां पर रख दे और बकरियां रख दे तो वह कैटिल ब्रीडिंग सेंटर हो जायगा और वह १००, २०० एकड़ का फार्म इस बिना पर एग्जम्प्ट हो जायेगा ।

जमीन के क्षेत्र में जैसाकि मेरे भाई ने कहा आज बिड़ला की उत्तरप्रदेश में ३०००० एकड़ के करीब जमीन शूगर फार्म्स की शकल में है और वह इस से छूट सकती है । लेकिन हमारी यह १०० एकड़ खेती की जमीन एग्जेम्प्ट नहीं हो सकती । आखिर यह कहां का न्याय है ? शहर वाले तो जा कर देहात में बसें और बिजनेस करें लेकिन बेचारे देहात वाले देहात में ही रहने के कारण मारे जाते हैं तो इस तरह की प्रवृत्ति देहात कब तक बर्दाश्त करेगा यह मेरी समझ में नहीं आता । आप इस भरोसे में मत रहिये कि वह हमेशा इस तरह के अन्याय को बर्दाश्त करता रहेगा । देहात वाला जब आवाज उठायेगा तो हमारे और आप के नीचे जमीन सरक जायगी । हम भले ही कितनी भी पूंजीपतियों की रक्षा करना चाहें, रक्षा नहीं कर पायेंगे ।

मुझे यह देख कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज कम्युनिस्ट ब्लाक करीब करीब खाली पड़ा हुआ है । शायद इस वजह से इस बिल पर नहीं बोलना चाहते हैं कि पहले इसी भद्दे और गलत रूप में यह बिल पास हो जाय और उस के बाद वे जनता में और गांवों में इस बिल के विरुद्ध प्रचार करें और सरकार के विरुद्ध जनता के असन्तोष को उभारें और इस तरह मौजूदा सरकार को

[श्री सिंहासन सिंह]

अपदस्थ कर के खुद हुकूमत की कुर्सी सम्हाल लें ।

मेरा खयाल है कि दफा २६ के मौजूदा शकल में रहते हुए और क्लाज १ जिस में कि म्युनिसिपल ऐरिया में शामिल जमीनों को इस कानून से एग्जम्प्ट किया जायगा, इस का असर जैसे मैं ने पहले कहा खेती की जमीनों पर गांव वालों की जमीनों पर असर पड़ेगा और यह जो भेदभाव शहर और गांव में किया जा रहा है यह अनुचित है । जो ज्यादा जमीन होगी वह गवर्नमेंट में वेस्ट हो जायगी । उस को लेने के बाद क्या करेंगे यह उन के अख्तियार में है । इस बिल में यह कहीं नहीं दिया गया है कि इस जमीन को गरीबों को, भूमिहीनों को दिया जायगा । मुमकिन है कि इस जमीन को पूंजीपतियों को दे दिया जाय जोकि इस को ज्यादा दामों पर बेचें । एक बार पहले भी ऐसा हुआ था कि दिल्ली के डेवेलपमेंट के लिये किसानों से डेढ़ आना और तीन आना गज के हिसाब से जमीन ली गई । मैं ने उस समय पार्लियामेंट में सवाल उठाया था । वही जमीन पूंजीपतियों को दी गई जिन्हों ने उस को ६ रुपये गज में बेचा । पता नहीं कि किसानों का दाम बढ़ाया गया या नहीं ।

एक माननीय सदस्य : बढ़ाया गया ।

श्री सिंहासन सिंह : तो कहीं ऐसा न हो कि इस जमीन को भी जोकि किसानों से चालीस गुना दे कर ली जाय बाजार भाव से बेचा जाय । अगर ऐसा किया गया तो किसान मर जायगा । मिनिस्टर साहब तो चले गये । मैं उन से अनुरोध करूंगा कि वे भी अभी इस बिल को पास न करावें । क्योंकि वह इस को माडल बिल बनाना चाहते हैं, इसलिये मेरा सुझाव है कि वे इस को फिर पार्टी में ले चलें और इस पर फिर विचार करने के बाद इस को यहां लाया जाय । इस की अभी कोई जल्दी नहीं है । इस बारे में नागपुर कांग्रेस ने प्रस्ताव पास किया था कि सन् १९५९ तक इस प्रकार का कानून लागू हो जाना चाहिये । लेकिन सन् १९५९ खत्म हो गया । अभी तक किसी प्रान्त में इस तरह का कानून लागू नहीं किया गया है । बंगलौर के कांग्रेस अधिवेशन में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया । फिर आप इस को माडल बनाना चाहते हैं । तो उचित है कि इस पर और विचार कर लिया जाय ।

मुझे पता लगा है कि उत्तर प्रदेश में भी एक ऐसा बिल तैयार हुआ है, अभी असेम्बली में नहीं आया है । कहा जाता है कि इस के अन्दर कोई एग्जेम्प्शन नहीं है । उस में मिल वालों को या पूंजीपतियों को कोई एग्जेम्प्शन नहीं दिया गया है । पता चला है कि इसलिये दिल्ली सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश की सरकार पर जोर डाला जा रहा है कि वह मिल वालों के बड़े बड़े फार्मों को और बगीचों को एग्जेम्प्ट करें । मैं नहीं कह सकता कि यह बात कहां तक सही है । लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर आप इस को माडल बनाना चाहते हैं तो इस पर विचार फिर करें ।

Mr. Chairman: I have rung the bell not once or twice, but four times. Now, the hon. Member must conclude. Shri Jaganatha Rao.

14 hrs.

Shri Jaganatha Rao (Koraput): Mr. Chairman, I wish to confine my remarks to three main points. These were raised mainly by you when you spoke the other day.

Firstly, you raised the question of the arbitrary powers of the competent authority. I find that the powers vested in the competent authority are

not wider than those of a civil court. If you read clause 21, it says that the Code of Civil Procedure shall apply. The right of appeal is provided for in clause 19, and the right of revision also is provided for in clause 20. So I do not see any reason why you should say that the competent authority becomes an arbitrary authority. On the other hand, if the jurisdiction is given to a civil court, matters will be delayed. Here we can have it disposed of quicker.

Secondly, you raised the objection that the invalidating of transfer is unconstitutional. As I read the Bill, it does not say that transfers are invalidated. It only says that the transfers will be disregarded or ignored. Transfers of land after the 10th February, 1959 would be disregarded or ignored. It is perfectly within the competence and jurisdiction of Parliament or the legislature to impose a moratorium on transfers.

I would like to refer to a recent decision of the Madras High Court—a judgment which was delivered day before yesterday and published in the *Statesman* of today. It upheld the sale of land and said that if the position was otherwise, the State would have prohibited the sale of land. The question arose there in a different way. The guardian of a minor disposed of the land, because a ceiling is going to be imposed by the State. The transfer was held invalid by the District Judge. On appeal, the High Court said that it is certainly open to a person to sell away land because a ceiling is going to be imposed. If this were not so, the State would have altogether banned all sale of land.

Here this Bill does not say that transfers are invalid or void. If it had said, so, different consequences would follow. Here transfer after a certain date is disregarded or ignored. So I do not think there can be any legal objection to that.

The third point is regarding compensation. Many hon. Members have questioned the adequacy and reasonableness of the compensation provided for in the Bill. But if you look at the provisions of the Bill, an Asami or sub-tenant is entitled to take the extra land and he has to pay compensation. That aspect has to be taken into account.

Secondly, we cannot bring in any comparison with prices prevailing in the Delhi Municipal area. That is, we cannot compare the prices in the urban area with those prevailing in the rural area. The two prices will naturally vary.

So when we consider the question of imposition of ceiling and payment of compensation, we have to look at the question in a different way. Then again, this is a model Bill in the only sense that a standard of 30 acres is being fixed as the ceiling. To that extent above, it will be a standard Bill and not for other matters.

But regarding compensation, the quantum varies from State to State. Therefore, if in Delhi a particular rate of compensation is prescribed, it does not mean that other States should also follow the same rate.

Dr. M. S. Aney (Nagpur): Why should not the acreage vary from State to State?

Shri Jaganatha Rao: 30 standard acres are considered to be quite sufficient for a family of five.

Dr. M. S. Aney: That depends on the nature of the land.

Shri Jaganatha Rao: True. But in the case of families having more than five members, there is a ceiling of 60 acres. The limit may be arbitrary in some cases. We cannot help it.

Another objection raised was that urban incomes and urban areas are excluded. That is true. There should also be a ceiling on urban income. But the fact that we do not have it now should not mean that we should

[Shri Jaganatha Rao]

not go ahead with land legislation which is long overdue. It has been the declared policy of Government, the Planning Commission and the Congress that we should proceed with land reforms. Therefore, I quite agree that we should proceed with the Bill as it has emerged from the Joint Committee.

श्री ब० प्र० सिंह (मुंगेर) : मैं ने भी इसके लिए अमेंडमेंट दिया था। मुझे भी बोलने का मौका दिया जाए।

Shri Kalika Singh (Azamgarh): I would like to have five minutes.

Mr. Chairman: The hon. Member is aware that the Deputy Speaker had said that the hon. Minister would be called to reply at 2 p.m. Now there is no time for any other hon. Member to speak.

Shri Achar (Mangalore): This point was raised the other day also. The Deputy-Speaker said that these three connected Bills might be discussed, if necessary, by extending the time.

Mr. Chairman: As a matter of fact, the time allotted for this Bill was only 3 hours. That limit was exceeded long ago. But in consideration of the fact that many hon. Members were anxious to speak, the Deputy-Speaker relaxed the limit and said that the three Bills taken together might be discussed for 9 hours. He was only anxious to see that Members had their say. Now, I am very sorry that I cannot give opportunity to other hon. Members.

Shri Achar: The point is that this is considered to be a model Bill.

Mr. Chairman: The hon. Member may or may not take it as a model Bill. The Bill does not say that it is a model Bill.

Shri Kalika Singh: May I propose an extension of time?

Mr. Chairman: There are many clauses to the Bill. Hon. Members will get an opportunity at that stage.

Shri Datar: I have listened very carefully to the fairly long debate on this Bill for two days and again today. As you are aware, there have been divergent opinions expressed on the merits of the Bill. And may I say with all deference that you have been one of the strongest and severest critics of this Bill? There are other hon. Members who have supported the provisions or the principles of the Bill, while reserving to themselves the right to criticise certain details. I have heard all these arguments with great respect and I should like to reply to the points, especially the important points, made by hon. Members, in the first place, to clarify doubts and in the second, to remove certain misapprehensions.

My hon. friend, Shri Tyagi, said that the Bill should be sent down to the various States for their consideration. I should like to answer this point first. Now, ever since popular governments assumed office at the Centre and in the States, the question of land reform in general and that of necessary land legislation in particular, has been before the country. May I also point out in this connection that as soon as the popular Ministries took over, they brought forward a number of Bills, and there has been, as the House will agree, considerable improvement especially upon the feudal conditions obtaining in various States?

Now, coming to the particular question of the ceiling and compensation, may I point out to my revered friend that this question was considered in all its details not only by the State Governments and Planning Commission but also by the National Development Council. In 1957, we had a meeting of the National Development Council which consists among others of the hon. Chief Ministers of various States. In 1957, it was accepted by the

Council that the question of land reforms, to the extent that it had not been implemented, and in particular, the question of ceiling, ought to be solved as early as possible, in an informal manner. It was pointed out that such a reform, namely, fixation of the ceiling on land ought to be finished before 1959 was out. That was the reason why we had to bring this Bill forward.

May I also point out that the question has not been approached hastily? It has been considered in all its details. When this Bill and the other two Bills were before this hon. House, before the matter was referred to Joint Committees, portions of the Planning Commission's scheme for the whole of India where this question was discussed and certain general recommendations had been made, were available to us.

Thereafter we had also a committee of the Panel on Land Reforms under the Chairmanship of hon. Shri Gulzari Lal Nanda which consisted of a number of hon. Members of Parliament amongst others. It came to certain conclusions which now form part of the present Bill. I, therefore, submit that this question has not been approached in a hurry. All the different aspects of the question have been considered. Naturally, when there is such an important question as land reforms, we have to proceed in certain respects rather slowly. This is in answer to my professor friend, Shri Sharma, who contended that the restrictions and exemptions almost outran the original provisions of the Bill. The object is that we have to hold the scales even to the extent possible consistent with the doctrine of social justice.

The second question that I should like to advert to is that we should not take landed property and other types of property on the same level. They are different types of property; and, let us not bring in the question of ceilings on other things. Lands are also an avenue for investment. In other cases, Government have taken a number of steps which are of a fairly socialistic nature.

Take the question of urban property. There are a number of taxes. You hove got income-tax and a number of other taxes to which the holders of such property are liable. That also should be taken into account. I would submit that no point should be raised on the ground tha. Government are trying to discriminate between the rural population and the urban population.

Incidentally, some hon. Members suggested that some ceiling should be fixed so far as the property within municipal or other areas was concerned. Is that a practical proposition? Are Government agriculturists? Government are holding certain lands for the benefit of the people—and such areas are few—and when there are certain tracts of agricultural land naturally, one has to note that if urbanisation has to go on, so far as that particular area is concerned, then, naturally, the rules regarding the ceilings on agricultural land cannot be applied in respect of agricultural property. Therefore, let us not make any distinction on that ground also.

14.14 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

So far as the present Bill is concerned, let us not try to say that this has been brought in for the purpose of striking a blow at the villagers. In fact, this Bill has been brought forward in the interests of the villagers. What is the interest of the villagers? That has to be taken into account. So far as the villagers are concerned, they are, a large number of them, landless labourers. Therefore, it is for their sake that the land has to be taken. There are landless labourers here and there in the rural areas. So far as they are concerned, this question of ceiling has to be placed for the purpose of having, to the extent that it is possible, excess land, not for

[Shri Datar]

government purposes at all but, generally, for the purpose of giving these lands to the landless agricultural people. That is one of the priorities that has been fixed.

I may also point out that agricultural lands should not be considered as merely a source of investment or profit. There is a distinction. Suppose I own a house or certain shares in a bank or something else, then, between myself and the income that I am likely to get, there is no other person at all. I invest the money and get the return. In that case other rules will apply. But, so far as landed property is concerned, you and I have to understand very clearly—even where there is a landlord who has leased the lands to others—that the interests of the actual cultivator of the land has to be fully protected and safeguarded. And, it is only for that purpose that, wherever it is possible, we are trying to get the excess land not for the purpose of using it for urban interests but only for the purpose of making such extra land available to the agricultural population. So, if this particular approach or objective is borne in mind, then much of the misapprehension is likely to disappear.

Then, the question arises whether this Bill is a model Bill. So far as this Bill is concerned, I may point out to my hon. friend Shri Tyagi that land is a State subject and it is for the State Legislatures to have legislation. In fact, in some of the States ceilings have already been effected. Therefore, we say only in a general way, that this Bill is a model one, in the sense that this Bill has been sponsored only so far as the territories of Delhi under the direct administration of the Central Government is concerned.

As my hon. friend, Shri Jaganatha Rao pointed out, it is open to the State Governments and to the State Legislatures to follow generally this prinicple. So far as the State Chief Ministers are concerned, they have agreed to follow the general principle, because, after all, we are anxious to evolve, consistently with variety, a general scheme by which the interests of the agriculturists and the interests of the landless people would be safeguarded as far as possible.

The next question is one of compensation. The question of compensation is, naturally, one which is bound to raise controversy. And, my hon. friend, Pandit Thakur Das Bhargava was one of our strongest critics so far as this Bill is concerned, in this respect. The question was considered by the working group and they came to certain conclusions which we are following. We also anticipated or forestalled the objection that there was going to be discrimination. There could be no question of discrimination at all. Here in this report of the Committee of the Panel on Land Reforms, on page 45, it has been stated:

"The second ground is social. The question is asked why the land sector alone should be selected for such discriminatory treatment. It is argued that land is property and the imposition of a ceiling takes the character of a capital levy on land and there is no proposal to extend it to other sectors. Either it should not be done at all or it should be accompanied by similar action in other sectors."

I have already replied partly to this particular objection. This is what the report says:

"Thus the imposition of a ceiling on land is in the national interest and, therefore, this steps has to be followed. But we realised that this involves a drastic curtailment of the property rights of a considerable number of landholders and considering the attachment in our present

society to income-producing property the feeling of injury on the part of the landed class as well as their demand that a similar limitation should obtain in other spheres can be easily understood. We do not, however, agree with the view that the imposition of a ceiling would be justified only if a similar limitation in incomes in other occupations were made simultaneously. Monopoly in land and the ownership of large areas by a small minority" and this may be noted, "of the agricultural classes is an obstacle to economic development".

"This does not apply with equal force to industrial development where large-scale organisation may lead to both greater economy and efficiency."

Shri B. K. Gaikwad (Nasik): What is that report?

Shri Datar: This is the report of the committee of the panel on land reforms.

Shri Tyagi: Were they all urban people or was there any agriculturist in that panel?

Shri Datar: There were a number of hon. Members, I believe, of Parliament also and officials and representatives of the State Governments.

An Hon. Member: Were there any agriculturists? That is the point.

Shri Datar: Sir, my time is short.. (*Interruptions.*) Land ceiling is fixed for the purpose of releasing some quantities of land. It is immaterial if the quantity is small in Delhi but the principle is to be followed and to that extent we say that this Bill is likely to be considered by the State Government as a model Bill because it is being passed by this sovereign legislature of the land. If this question is approached in this way, in a number of difficulties would have been averted.

I have noted the strong feeling expressed by a number of hon. Members about the compensation that is being given which is forty times the land revenue. Most of the hon. Members who raised this question were not aware of the fact that Government are not taking land or acquiring land for their own purposes. The excess of land taken from persons who have more than the ceiling fixed has to go back to the landless people and other people and they will have to pay the compensation. In our desire to give more money to the owners of such lands, if we raise the expenditure on compensation, these people who are 99 per cent agriculturists, if not 100 per cent, will have to bear the burden of compensation. That fact should not be forgotten....

Pandit Thakur Das Bhargava (Hissar): It is robbing Peter to pay Paul.

Shri Datar: There is no question of Peter and Paul. The decision was taken by the National Development Council and the ceilings have been fixed.... (*Interruptions.*) Let not my hon. friend at this stage try to question the propriety of what all the State Chief Ministers and others have decided in 1957. The question is before the country and the principles of compensation have to be decided by Parliament. Government is only an intermediary agency. All this excess land has to go to those people and they have to bear the burden. There is no question of Peter or Paul; both are agriculturists and are in the village and land is not going to be taken for urban purposes. Let us not, in our vehemence, create a new discrimination between the urban and the rural population or between the owners of land and others. The object is to take this land only for the purpose of giving it to others. You cannot expect the Government to bear the financial responsibility for taking this land and giving it to others. That was one of

[Shri Datar]

the decisions taken by the National Development Council that all this is to be done without involving the Government in any financial commitments because Government have a number of welfare schemes to be carried through. We have tried to follow that principle to the fullest extent. I would incidentally mention that the then Delhi Legislature was the first to come into the field and it had an Act passed as early as 1954 and there they gave only twenty per cent. of the land revenue as compensation. Here, we have increased it. It is true that a number of hon. Members have expressed themselves very strongly against what they call the inadequacy of compensation but I may point out that it is our desire to see to it that everything is done in as equitable a manner as possible.

Shri Raghunath Singh (Varanasi): Is this an equitable manner to pay more to princes and moneyed men?.. (*Interruptions*).

Shri Tyagi: He shall be guided by the vote of the House.... (*Interruptions*).

Shri Datar: I strongly repudiate the suggestion that this has been done against the interests of the rural population. It is true that this would benefit the agriculturists and there are only a few landlords affected; the number is immaterial whether it is 30 or 55. The principle is this that land is being taken not for using it for other purposes but only for the purpose of giving it either to the landless labourers or using it in their interests. If this aspect is fully appreciated, much of the opposition would disappear.... (*Interruptions*).

Certain objection was taken that the Chief Commissioner has been given the largest powers. He is the head of the Delhi Administration and responsible to the Government of India and so the highest officer has been invested with certain powers. The hon. Members did not read clause 26 properly. You cannot have exemption in respect of certain things which you have done after a certain date. If on the date of this Bill, there are certain things done which are in the interest of the nation, for the purpose of producing more in agriculture, etc., there is a proviso. If the land is being used as a specialised farm, it will be exempted. You cannot have a new farm now. If it is being used for cattle breeding, dairy or wool raising, the provision is there. Some hon. friends raised the question of horse breeding. I am afraid that it has nothing to do here because the hon. Member has not properly looked into this. The first provision is in the larger interests of the nation, in the interest of the agriculturists themselves when they are carrying on certain large works, organised works on their land. That will apply if they had been doing so even before this Bill was there. Then it will be taken into account. It does not mean that exemption is going to be given to all the people to have specialised farms or to have subterfuges by which they can claim exemption. I may also point out that there has been a provision for the withdrawal of exemption. In these circumstances, there is no force in contending that all this is being done to help what they call capitalists in agriculture; that is entirely wrong. My hon. friend has pointed out that a particular date has been mentioned. We did not create a moratorium in the largest sense. We say that when it was first announced by the hon. Home Minister that a Bill for laying down ceilings on acquisitions would be brought forward, that constitutes a material date because people are likely to take advantage of the period between the announcement and the bringing forward of this Bill. We may have a number of transactions for bypassing if not defeating, the provisions of this Bill and that is the reason why we have taken it back by only one year and not more. There also we have followed the usual principles of what are known as equities associated with *bona fide* transfers for

value. The hon. House is aware that certain equitable principles have been evolved and those principles have been followed. We have not invalidated these transfers at all. What we have stated is that for the purpose of getting the excess land these transactions or such transactions will be disregarded where it becomes necessary. Otherwise, Sir, if there is a transfer for value, a *bona fide* transfer, then, naturally, we have followed the principle of, what is known as, equitable contribution by the owner, by the transferer himself as also the transferee.

Then, there is no particular point so far as "family" is concerned. It is entirely wrong for the hon. Members to have suggested that we have made a departure from the Hindu law. What has been done is this. In this country, a family is an operative agricultural unit and normally it consists of five persons. Therefore, the rights under the Hindu law are not affected at all. If the sons or brothers are entitled to a share, either they can form their own units or they can join or merge with this unit. In those cases, you will find that there will be two or more units. Therefore, nothing has been done to take away what is due to a Hindu family.

This has to be understood, that normally the man, his wife and certain other persons constitute what can be called a normal operative agricultural unit, and it is for that purpose that this figure has been fixed. It does not take away the rights under the Hindu law or any other right, nor does it take away the right of forming an independent unit.

Shri Tyagi: Why has discrimination been made between a minor son and a major son?

Shri Datar: That is because he is a dependant on the man concerned, and the moment he becomes independent, he can have his own unit.

Sir, I have tried, as humbly as possible, to deal with the points raised and also give the necessary clarifications. I have also tried to clear the misapprehensions to the extent it is necessary. This is, as I have said, one of the important Bills, and Government have purposely brought it forward with a view that we should have the advantage of the opinion of the highest legislative body in the land. I am quite confident that it will benefit the poor agricultural people to the small extent that it can so far as Delhi territory is concerned. But I am also confident that similar and proper Bills will be brought forward and passed by the State legislatures as early as possible, because the object underlying this land reform is highly important and, may I add, in the interests of the agriculturists themselves.

Pandit Thakur Das Bhargava: With your permission, Sir, may I put one question? What is the average amount of land revenue per acre in Delhi? If you could kindly tell us that we may know what will be the compensation.

Shri Datar: The compensation is 40 times the land revenue. There may be, I believe, some cases where it will be less than a rupee so far as an acre is concerned, but the highest, if I mistake not, is Rs. 4 to Rs. 6 per acre—I am pointing out in a general way. It is true that we have considered the question of compensation in terms of land revenue, but the House is also aware that under the new law the rent that a tenant will have to pay is also calculated or assessed in terms of the multiples of land revenue, and that is a matter which has to be considered.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That the Bill to provide for the imposition of a ceiling on land holdings in the Union territory of Delhi and for matters connected therewith, as reported by the Joint Committee, be taken into consideration."

The motion was adopted.

Mr. Deputy-Speaker: We will continue the discussion next time. We shall now take up the next item of business.